(c) In view of the above, the question does not arise.

(d) GDR, Poland, U.K. and several other countries have offered to sell ships to Indian shipping companies.

(e) Details of such proposals are discussed between the purchaser and the buyer. As no Indian Shipping Co. has shown much interest to buy new foreign vessels, no details are reported to have been discussed so far.

दिल्ली में प्लास्टिक कारखानों में संकट

*962. **डा० महादीपक सिंह शाक्य :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लास्टिक कार्यों में लगे हुए दिल्ली में हजारों छोटे कारखानों को संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या ये कठिनाइयां वितरण केन्द्रों द्वारा उत्पन्न की गई हैं ;

(ग) क्या ये केन्द्र नियमित रूप से माल सप्लाई नहीं कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). (क) भाग के उत्तर के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठते।

Regularisation of Capacity of Cadbury India Ltd.

*963. SHRI PRASANNBHAI MEHTA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether multi-national company Cadbury India Limited, manufacturing chocolates and other processed foods, have applied to Government for regularisation of these capacities and are still awaiting approval;

(b) if so, the main reasons for delay;

(c) when the final decision in this regard is likely to be taken;

(d) whether some of the companies manufacturing the same have been found to manufacture more than the licensed capacity; and

(e) if so, what action has been taken against them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) to (c). M/s. Cadbury India Limited applied for endorsement of productive capacity on the Registration Certificate in respect of Chocolates, Drinking Chocolate and Cocoa Powder and a final decision in this regard has already been taken.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

दैनिक पत्रिका "अवन्तिका" को अखबारी कागज का कोटा

*964. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री 22 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 274 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दैनिक पत्रिका "अवन्तिका" ने अपनी वितरण संख्या के आंकड़े बढ़ा-चढ़ा कर दिखाकर वर्ष 1974–75, 1975–76, 1976–77 और 1977–78 के दौरान दृश्य एवं श्रव्य प्रचार निदेशालय से बड़े पैमाने

पर विज्ञापन प्राप्त किये थे और यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उसे कितने मूल्य के और कितने विज्ञापन दिये गये ;

(ख) ऐसे विज्ञापनों के हकदार बनने के लिए कितनी ग्राहक संख्या आवश्यक है और उनका मूल्य-कितना है और दी गई वितरण संख्या जांच करने के बाद कम पाये जाने पर सरकार द्वारा किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस समाचारपत्र के मालिक, उद्योगपतियों, सरकारी अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और राजनैतिक नेताओं पर कीचड़ उछाल रहे हैं और यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) दैनिक "अवन्तिका" को विज्ञापन प्रचार की आवश्यकताओं के अनुसार जारी किए गए थे । जहां तक विज्ञापनों का मूल्य और उनकी संख्या का सम्बन्ध है, वैयक्तिक समाचारपत्रों को जारी किए जाने वाले विज्ञापनों की मात्रा प्रकट करना सरकार की नीति नहीं है ।

(ख) वर्तमान विज्ञापन नीति के अनुसार, समाचार पत्र नियतकालिक पत्र सरकारी विज्ञापनों के पात्र हैं यदि उनकी प्रति प्रकाशन दिवस न्यूनतम प्रसार संख्या 2,000 प्रतियां हों, सिवाय कुछ कतिपय विनिर्दिष्ट श्रेणियों के पत्रों के जिनके लिए कम प्रसार संख्या निर्धारित है । यदि किन्हीं समाचारपत्रों नियतकालिक पत्रों द्वारा बताई गई प्रसार संख्या गलत सिद्ध होती है तो उनको विज्ञापनों के लिए अपात्र समझा जाता है । इसके अतिरिक्त, उनके विरुद्ध ऐसी अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है, जो सरकार उपयुक्त समझे ।

(ग) सरकार के पास इस प्रकार की जानकारी नहीं है ।

Salt Cess collected from Gujarat

*965. SHRI ANANT DAVE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Rs. 8.50 crores have been collected from the Gujarat State as salt cess;

(b) the amount utilised during the last three years for development of this industry for roads, for water supply and for welfare of employees of this industry; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) The amount accumulated on account of salt cess as on 31-3-1977 was Rs. 12.81 crores. Statewise figures of salt cess accumulations are not maintained.

(b) The amount utilised out of the salt cess proceeds on various development and labour welfare works and related items during the last three years was as follows:

1974-75	7,24,025
1975-76	5,85,332
1976-77	18,29,332

(c) Does not arise.

Medium for NDA and Combined Defence Services Examination

*966. SHRI BALAK RAM: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether medium for NDA and Combined Defence Services examination and interviews still continues to be English despite public pressure to switch over to Hindi or regional